

नेत्रदान पखवाडे के अवसर पर प्रश्नोत्तरी
एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित



जयपुर टाइम्स

अलवर(निस.)। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि नेत्रदान पखवाडे के अवसर पर राजकीय नरसिंग कॉलेज में प्रश्नोत्तरी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेजिडेंट चिकित्सकों जैनएमटीसी, वैश्वसी नरसिंग, एनएमटीसी कॉलेज के छात्र-छात्राओं में भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में नरसिंग छात्रा पूजा यादव का प्रथम पुरस्कार, मौनिका यादव का द्वितीय पुरस्कार एवं खुशी का तृतीय पुरस्कार हुए चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अधिकारी डॉ. शिवाजी थेरेन ने नेत्रदान के विषय पर प्रवित्र से जानकारी दी। इस दीवान डॉ. मधुप्रदीप सक्सेना, डॉ. दीपा जेन, नरसिंग कॉलेज के प्राचार्य एवं स्ट्राफ मौजूद रहा।

**अतिवृष्टि से अलवर एवं राजगढ़ तहसीलों
में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत
हेतु 691.52 लाख रुपये की राशि के
प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए**

जयपुर टाइम्स

अलवर(निस.)। अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. अर्थिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरवाड अधिकारियों को बैठक लेकर ई-गिरिदारी, समर्क वर्ष एवं एनएफएस के संबंध में आवाहन किया। जिला कलक्टर ने बिन्दुवार समीक्षा कर उत्तरवाड अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खाद्य स्वयं के अवगत कराया

राजस्थान संपर्क पोर्टल व
अन्य माध्यमों से प्राप्त
परिवेदनाओं का त्वरित व
गुणवत्ता के साथ
निस्तारण करें - जिला
कलक्टर
जयपुर टाइम्स



की समीक्षा कर निर्देश दिये कि आमजन की परिवेदनाओं का समाधान त्वरित गति से गुणवत्ता के साथ किया जावे। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रतीक्षित संबंधित अधिकारियों पोर्टल का अपलोड करें। उन्होंने गुणवत्ता के अधिकारियों के लिए निस्तारण में विभिन्न समझौता नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम व अन्य जनसुनवाई से प्राप्त परिवेदनाओं का भी गुणवत्ता के साथ त्वरित विवरण किया जावे। जिला कलक्टर ने राजस्थान कार्यक्रमों का विवरण पुरस्कार करने के तहत राजस्थान के तहत गिरिदारी व एकार्सी में जिले में अचूकी प्राप्ति हुई है। लिंगवत 95 हजार गिरिदारी कार्यों में से 80 हजार कार्य 15 दिवस में निस्तारित कर दिए गए हैं, शेष 9 हजार गिरिदारी कार्य को आगामी दो दिवस में पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अतिवृष्टि के कारण होने वाले फसल खराब की स्थिति में कारकारों की भूमि की समयवाद ई-गिरिदारी कराना सुनिश्चित करें। इस उन्होंने उत्तरवाड अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में भारी वर्षा को दृष्टिगत रूप से हुए यह सुनिश्चित करें कि जलशयों, बांध, पानी, जोड़, झारनों, नदियों के बहाव क्षेत्र एवं बरसाती नावों आदि स्थानों पर सुक्षमतम् उपरांग पुरुष रखते रहें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि जिला कलक्टर ने राजस्थान के तहत गिरिदारी व एकार्सी में विभिन्न विवरण किया जावे। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ सालुखे गैरव रवीन्द्र, एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल, एडीएम द्वितीय योगेश डानगुर, एसटीएम अलवर मायर भारदाज, प्रशिक्षु अंडाएस एस्टर्वर्म प्रजापति, डीएसओ विनोद जुनेजा सहित वीसी के माध्यम से समस्त उत्तरवाड अधिकारी जुड़े।

**झालावाड में छठ गिरने से सात बच्चों की मौत पर सरकार
की संवेदनहीनता कि विधानसभा में बच्चों को श्रद्धांजलि
तक नसीब नहीं हुई- नेता प्रतिपक्ष जूली**

जयपुर टाइम्स



जयपुर(कास)। जिला कलक्टर डॉ. अर्थिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरवाड अधिकारियों को बैठक लेकर ई-गिरिदारी, समर्क वर्ष एवं एनएफएस के संबंध में आवाहन किया। जिला कलक्टर ने बिन्दुवार समीक्षा कर उत्तरवाड अधिकारियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव जिला स्वरीय कमेटी से अनुमोदन प्राप्त राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमएस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख, 22 पंचायत भवनों हेतु 41 लाख रुपये 9 पुलियाओं हेतु 5.40 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निजी आवासीय भवनों के नुकसान के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमएस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख, 22 पंचायत भवनों हेतु 41 लाख रुपये 9 पुलियाओं हेतु 5.40 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निजी आवासीय भवनों के नुकसान के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमएस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख, 22 पंचायत भवनों हेतु 41 लाख रुपये 9 पुलियाओं हेतु 5.40 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निजी आवासीय भवनों के नुकसान के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमएस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख, 22 पंचायत भवनों हेतु 41 लाख रुपये 9 पुलियाओं हेतु 5.40 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निजी आवासीय भवनों के नुकसान के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमएस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख, 22 पंचायत भवनों हेतु 41 लाख रुपये 9 पुलियाओं हेतु 5.40 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निजी आवासीय भवनों के नुकसान के प्रकरणों में नियमानुसार जाँच करकर प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए हैं, जिनमें 218 विवाहार्यों हुए 436 लाख, 45 आयोजनावाडी केंद्रों हेतु 109.50 लाख, 8 व्यास्थायों केंद्रों हुए 16 लाख, 35 सड़कों वारिश होने पर एसटीआरएफ नॉर्मस अंतर्गत शक्तिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु बुल 691.52 लाख रुपये की राशि के प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार सरपर पर स्वीकृत होने पर इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत की जीवनी उत्तरवाड अधिकारी के निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके 24 घण्टे में 90 एमए

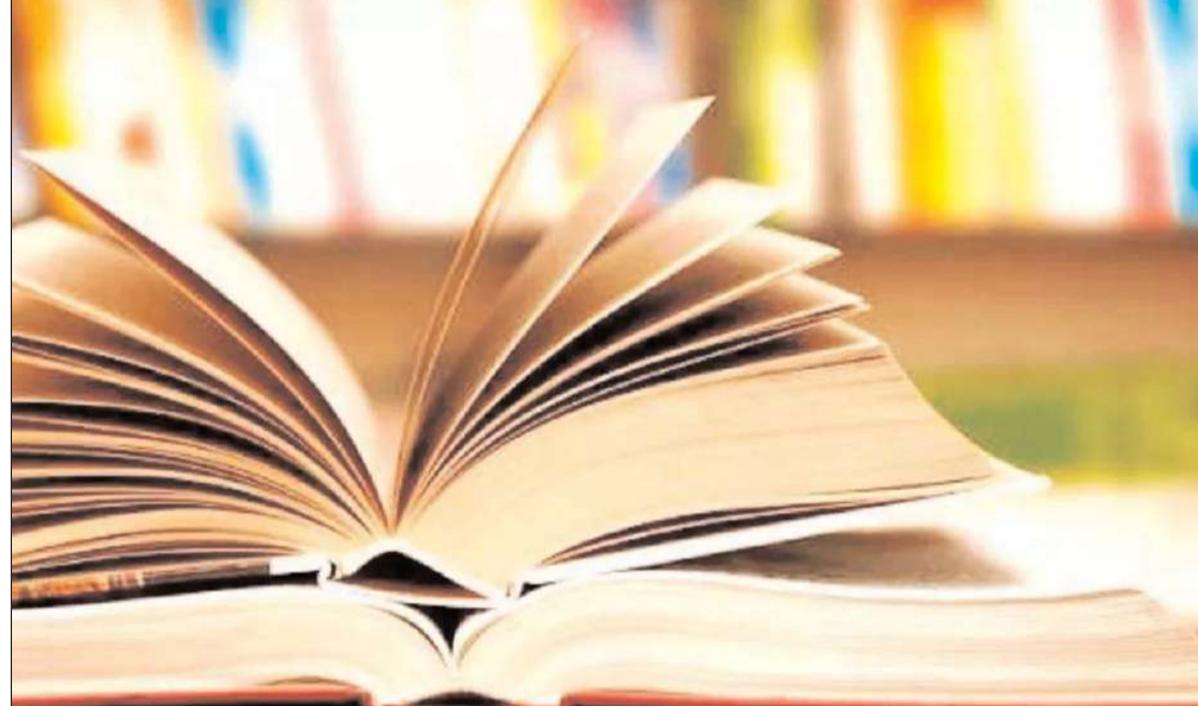
ट्रूप रूपी आपदा को अवसर में बदलें



चूंकि सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियां एच-1बी वीजा के जरिये ही अपने प्रशिक्षित कर्मचारी अमेरिका भेजती हैं, इसलिए ट्रंप सरकार इसी पर अंकुश लगाना चाहती है। हालांकि खुद ट्रंप के कारोबार में एच-1बी वीजा पर आए पेशेवर काम करते हैं, पर उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस को एच-1बी वीजा की व्यवस्था घोटाला नजर आती है। गवर्नर डेसेंटिस ने तो यहां तक कहा है कि भारत ने इसे अमेरिकी व्यवस्था का दोहन करने का कुटीर उद्योग बना रखा है। ट्रंप सरकार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एफ वीजा और एक्सचेंज छात्रों के जे वीजाओं पर भी कड़ी समय सीमाएं लगाने जा रही हैं। ग्रीन कार्ड की जगह भी 50 लाख डालर से मिलने वाले गोल्ड कार्ड शुरू किए जा रहे हैं जिनके सहारे ट्रंप अमेरिका के कर्ज को उतारना चाहते हैं। व्यापार और आप्रवासन को लेकर ट्रंप सरकार का यह रवैया भले नाटकीय लगे, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। उनके पहले कार्यकाल के कामों

पं चतुर्व की कथा है। एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थीं-अनागतविधाता, प्रत्युपन्नमति और यद्विविध। अनागतविधाता आने से पहले उपाय कर लेती थी। प्रत्युपन्नमति समस्या आने पर कृष करती और यद्विविध भाव्य के भरोसे रहती थी। चीन को आप अनागतविधाता मान सकते हैं और भारत को प्रत्युपन्नमति, जो संकट सिर पर आने पर ही अपने हाथ-पांव मारता है। हम आजाद तो गांधी जी के स्वावलंबन के नारे के साथ हुए थे, मगर अन्न की आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति पर काम तब तक शुरू नहीं किया गया जब तक भयंकर अन्न संकट से दो-चार नहीं हुए। आर्थिक सुधार तब तक नहीं किए, जब तक 1991 में देश संरक्षणवाद और लाइसेंस राज की वजह से दिवालिया होने के कागार पर नहीं जा पहुंचा। इसी तरह उद्योगों में आत्मनिर्भरता की बात हमें तब तक याद नहीं आई जब तक कोविड महामारी ने आर्थिकी को ठप नहीं कर दिया। अब ट्रॉप की अप्रत्याशित नीति ने विदेश व्यापार और विदेश नीति के मोर्चे पर हमारे लिए संकट खड़ा कर दिया, जिसके समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराई जा रही है। टैरिफों को अपनी ही केंद्रीय अदालत द्वारा अवैध ठहराने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रॉप ने 25 वर्षों के सामरिक और आर्थिक सबधांओं को ताक पर रखते हुए भारत पर लगाए टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यहीं नहीं, भारत के सेवा क्षेत्र की निशाना बनाने वाले मोर्चे भी खोले जा रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस हर साल प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए 65 हजार और उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार वीजा देती है जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीय पेशेवर और छात्र हासिल करते हैं। चीनीक सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनियाँ एच-1वी वीजा के जरिये ही अपने प्रशिक्षित कर्मचारी अमेरिका भेजती हैं, इसलिए ट्रॉप सरकार इसी पर अंकुश लगाना चाहती है। हालांकि खुद ट्रॉप के कारोबार में एच-1वी वीजा पर आए पेशेवर काम करते हैं, पर उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और फ्लोरिडा के गवर्नर रान डेसेंटिस को एच-1वी वीजा की व्यवस्था घोटाला नजर आती है। गवर्नर डेसेंटिस ने तो यहां तक कहा है कि भारत ने इसे अमेरिकी व्यवस्था का दोहन करने का कुटीर उत्थान बना रखा है। ट्रॉप सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एक वीजा और एक्सचेंज छात्रों के जेवीजाओं पर भी कड़ी समय सीमाएं लगाने जा रही है। ग्रीन कार्ड की जगह भी 50 लाख डालर से भिन्न वाले गोल्ड कार्ड शुरू किए जा रहे हैं जिनके सहारे ट्रॉप अमेरिका के कर्ज को उतारना चाहते हैं। व्यापार और आप्रवासन को लेकर ट्रॉप सरकार का यह रवेया भले नाटकीय लगे, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। उनके पहले कार्यकाल के कामों से और चुनाव प्रचार से इसके स्पष्ट संकेत मिल चुके थे। भारत की ऊंची आयात-शुल्क दरों और एच-1वी वीजा के मामले पर ट्रॉप के पिछले कार्यकाल में भी तनातनी हुई थी। भावी और अत्याधिनिक तकनीक को लेकर उनका संरक्षणवादी रवेया भी नया नहीं है, मगर भारत ने समय रहते इनसे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। क्र्यशक्ति, उपभोग और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंडी है। उसमें भिले प्रवेश का भारतीय व्यापारियों ने सामर्थ्य के हिसाब से पूरा लाभ उठाया, लेकिन क्या हम ऐसी वैकल्पिक मंडी तैयार कर पाएं जहां भारतीय व्यापारी अमेरिका में राजनीतिक या आर्थिक अडचनें खड़ी होने पर अपना माल बेच सकें। यूरोपीय संघ की मंडी अमेरिका का एक अच्छा विकल्प बन सकती थी। चीन ने मौजूदा हालात का पूर्वानुमान करते हुए यूरोप के साथ अपना व्यापार अमेरिका से भी अधिक बढ़ा दिया, परंतु भारत पिछले तीन साल से यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अटका हुआ है। चीन ने अपना व्यापार आसियान की मंडियों में भी फैलाया इसीलिए जब ट्रॉप ने टैरिफ की धमकी दी तो चीन ने वाक् युद्ध में न उलझते हुए पहले बराबर का टैरिफ लगाकर और फिर उच्च प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों और चुंबकों के निर्यात को रोककर ट्रॉप को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत भी अब यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यापार बढ़ाने और रक्षा, ऊर्जा, चिकित्सा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मई 2020 में इसी के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, पर क्या उससे कृच्छ्र प्रगति हुई? प्रत्युपन्नमति मछली की तरह संकट मंडाने पर जरूर हम कृच्छ्र सुधार करते हैं। कृच्छ्र के नाम लेते हैं, पर संकट टलने के बाद भूल जाते हैं। जरूरत उहें जारी रखने की है। प्रधानमंत्री ने जापान में उद्योगपतियों से कहा 'कम, मेक इन इडिया,' लेकिन क्या उसके लिए हम जरूरी आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, श्रम सुधार और कार्यसंस्कृति के सुधार करने के लिए तैयार हैं? जापान में हड्डताले न के बराबर होती हैं और तोड़फोड़ नहीं होती। क्या भारत में ऐसी कार्यसंस्कृति संभव है? सुधारों की जरूरत कृप्ति और सार्वजनिक क्षत्रों में भी है। चीन ने अपने इंजन बनाकर छठी पांची के लड़कू विमान तैयार कर लिए हैं। जबकि हमें विदेशी इंजन लगाकर भी तेजस को बनाते-बनाते 40 बरस बीत गए हैं। चीन अपना सामान बनाने में स्वचालन, एआई या यंत्रबूद्धि और प्रशासन की निगरानी में इष्टतम प्रक्रिया का प्रयोग करता है। दुनिया की मंडियों में उसके माल से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को उससे भी कुशल उत्पादन प्रक्रिया अपनानी होगी। आर्थिक सुधारों को 35 साल हो रहे हैं, पर क्या हम एक भी ऐसा ब्रांड बना पाएं हैं जो अमेरिका, जापान, जर्मनी और कोरिया के ब्रांडों की तरह वैश्विक हो?

एनसीईआरटी की पहल पर आपत्ति क्यों?



इतिहास की घटनाएं वर्तमान को दिशा देती हैं और वर्तमान उनसे सबक लेकर भविष्य की सुदृढ़ नींव रखता है। दुर्भाग्य से हमारे विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास और पाठ्यपुस्तकों में घटनाओं और तथ्यों को प्रायः यथार्थ से काटकर मिथ्या आदर्शों, भावुक नारों और दलगत पूर्वग्रहों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। जब भी इतिहास को प्रामाणिक और वस्तुपरक ढंग से लिखने या पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसे अनावश्यक विवाद और शोर-शराबे का समाना करना पड़ा। सुधारों की इसी पृष्ठभूमि में एनसीईआरटी ने विभाजन की विभीषिका और उससे उपरी त्रासदी को निष्पक्ष दृष्टि से समझाने के उद्देश्य से कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दो विशेष पूरक शैक्षक माड्यूल जारी किए हैं। इन्हें अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि चर्चा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों की सूक्ष्म और गहन समझ विकसित की जाएगी। इन माड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना, लार्ड माउटबेटन और कांग्रेस को विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है। कौन नहीं जानता कि जिन्ना की अंधी महत्वाकांक्षा, पर-लोलूपता और पृथक पहचान की राजनीति ने भारतीय मुसलमानों में पनप रही सांप्रदायिक भावना को भड़काने में निर्णायक भूमिका निभाई। विभाजनकारी राजनीति के बीज पहले से ही सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इस्माइल जैसे नेताओं के विचारों में मौजूद थे। इस्लाम से पोषित धा स्थायी या समान सिद्धांत: नकारता जिस इस्लाम की सवि हो, उसे मानने वा आबादी वाले पंथनिरा 20वीं शताब्दी के नेताओं के लिए पृथक् स्वर ही सुनाई पड़ते थे। प्रस्ताव के बाद मु विभाजन की मांग क लगा। 16 अगस्त 1947 'डायरेक्ट एक्शन डे' तय कर दी। केवल व कई हजार लोग म (बंगाल) में 10 अक्टू द्वृसैनी के नेतृत्व में नियोजित नरसंहार ; मुस्लिम लीग की अ सुहरावर्दी मुख्यमं ना आखाती का न उन्माद का परिणाम षड्यन्त्र था। जिन्ना अं बंटा भारत या बर्बाद कांग्रेस नेतृत्व ने मुसलमानों के बड़े त में सफल रहे कि न

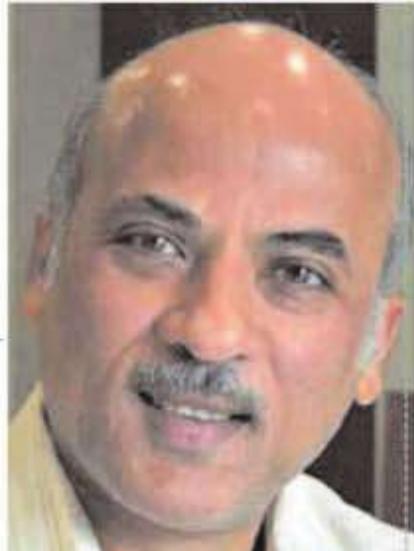
विचारों में मौजूद थे। उनका सोच उस राजनीतिक इस्लाम से पौष्टि था, जो गैर-मुसलमानों के साथ स्थायी या समान संबंध की संभावना को सिद्धांततः नकराता था। इनका मानना था कि जिस इस्लाम की सादियों तक भारत में हुक्मत रही हो, उसे मानने वाले मुसलमान बहुसंख्यक आवादी वाले पर्याणरपेक्ष भारत में कैसे रह सकेंगे? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मुसलमान नेताओं के लिए पृथक देश की मांग के छिपटुपट स्वर ही सुनाई पड़ते थे, किंतु मार्च 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग के नेतृत्व में विभाजन की मांग को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा घोषित 'डायरेक्ट एक्शन डे' ने विभाजन की दिशा लगभग तत्त्व कर दी। केवल कलकत्ता (कोलकाता) में ही कई हजार लोग मारे गए, जबकि नोआखाली (बंगाल) में 10 अक्टूबर 1946 को गुलाम सरवर हुसैनी के नेतृत्व में निर्दोष-निःस्त्र हिंदुओं का पूर्ववर्ती नियोजित नरसंहार हुआ। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की अतरिम सरकार थी और हुसैन द्वारा दो मुख्यमंत्री मुहम्मद अली और हुसैन द्वारा दो अमीर थे। नोआखाली का नरसंहार किसी आकर्षित उन्माद का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित घटयंत्र था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की धमकी-बंद भारत या बर्बाद भारत' के समक्ष तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने घुटने से टेक दिए। जिन्ना मुसलमानों के बड़े तबके को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि मत-मजहब, संस्कृति, रीति-

रिवाज, इतिहास और जीवन-दृष्टि जैसे सभी आधारों पर वे हिंदुओं से स्थायी रूप से भिन्न हैं। यही कारण था कि 1946 के सविधान-सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आक्षित 78 में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त की। मुस्लिम लीग को मद्रास, बाबौ प्रेसीडेंसी और उड़ीसा में करीब सौ प्रतिशत, बंगाल में 95 प्रतिशत, मध्य भारत में 93 प्रतिशत, असम में 91 प्रतिशत, अविभाजित पंजाब में 86 प्रतिशत, बिहार में 85 प्रतिशत और संयुक्त प्रांत में 82 प्रतिशत सीटें प्राप्त हुईं। जिन तमाम मुसलमानों ने मजहब के आधार पर पृथक देश की मांग का समर्थन किया, उनमें से बड़ी संख्या में विभाजन के बाद भी भारत में ही रह गए, जबकि पाकिस्तान से भारत आए लगभग डेढ़ करोड़ हिंदू, सिख और सिंधी अपने ही देश में शरणार्थी बनकर दर-दर भटकते रहे। विभाजन से उपजी हिंसा में लगभग दस लाख से अधिक निर्दोष लोग मारे गए, लाखों परिवार अपने पुरखों की जमीन-जायदाद से उजाड़ दिए गए और माताओं-बहनों के विरुद्ध हुए अत्याचारों ने पाश्चात्काता और अमानुषिकता की सारी सीमाएं पार कर दीं। मानव इतिहास का यह सबसे बड़ा विस्थापन किसी प्राकृतिक आपदा या बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ। इसके लिए अपने ही लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। 1942 के क्रिप्स मिशन और 1946 के कैबिनेट मिशन में विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं था, फिर भी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना तुरंत क्यों स्वीकार की गई।

वैज्ञानिक नजरिए की जमीन

विज्ञान शिक्षण का एक अहम आयाम यह भी है कि छात्र किसी घटना पर समालाचनात्क ढंग से सोचें। सामाजिक मान्यताओं पर विर्मश करें, उन पर सवाल उठाएं। नीतिगत स्तर पर हम आज विज्ञान शिक्षण को लेकर काफी ऊपर उठ चुके हैं, मगर क्रियान्वयन के स्तर पर पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था विज्ञान को एक प्रक्रिया न समझते हुए सीधे-सीधे जानकारियां परोस कर नींव को कमज़ोर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। विज्ञान की कक्षाओं में जिन अवधारणाओं पर छात्र काम करते हैं

अ द्वाईस फरवरी को देश के शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान को लेकर एक खास प्रकाश की हलचल दिखाई देती है। यही वह दिन है, जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का रहस्य खोजा था, जो 'रमन प्रभाव' के नाम से जाना जाता है। रमन की खोज देशज उपकरणों के जरिए एक अनवरत प्रक्रिया का परिणाम थी। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में सन 1986 से हर साल सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे शैक्षणिक संस्थान चाहे वे स्कूल हों या महाविद्यालय-विश्वविद्यालय, रमन और उनके कार्य को एक औपचारिक कार्यक्रम के तहत याद करते हैं। पर दिवस की मानसिकता से परे जाकर बेशक अब समीक्षा करने और सवाक लेने का वक्त है कि देश को वैज्ञानिक नजरिए से लैस करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। स्कूलों में माध्यमिक कक्षाओं के स्तर से ही विज्ञान शिक्षण एक अनिवार्य अंग है। विडंबना कहें कि हमारे देश में स्कूली स्तर पर 'कथनी और करनी' में काफी फ़र्क दिखाई देता है। एक तरफ हम रमन को याद करते हैं वहाँ अगले ही पल उनके वैज्ञानिक नजरिए, पद्धति और विज्ञान शिक्षण संबंधी विचारों को हाशिए पर पटक कर देकियानुसू रास्ते पर चलने लगते हैं। आजादी के बाद हमारे यहाँ विज्ञान शिक्षण में विज्ञान के लोकव्यापीकरण की बातें तो काफी की गईं, मगर वे मुख्यधारा शिक्षा का अहम हिस्सा नहीं बन पाईं। बच्चे स्कूलों में विज्ञान को रट कर पढ़ने पर मजबूर हैं। विज्ञान की तासीर है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया में अवलोकनों, प्रयोगों और खोजबीन को माध्यम बना कर विज्ञान सीखें। विज्ञान शिक्षण का एक अहम आयाम यह भी है कि छात्र किसी घटना पर समालोचनात्क ढंग से सोचें। सामाजिक मान्यताओं पर विर्माश करें, उन पर सवाल उठाएं। नीतिगत स्तर पर हम आज विज्ञान शिक्षण को लेकर काफी ऊपर उठ चुके हैं, मगर क्रियान्वयन के स्तर पर



**सलमान के साथ
एकशन फिल्म
करना चाहते थे
सूरज बड़जात्या**

फिल्म डायरेक्टर सूरज बड़ाजात्या ने कहा है कि सुपरस्टार सलमान खान के लिए ऐसा काम करना जो आज के समय में रिलेवेंट और नया लगे, हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। बड़ाजात्या सलमान के साथ एक एपशन फिल्म बनाने की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने यह आइडिया छोड़ दिया वर्णोंकि वह सलमान के लिए सही केरेक्टर नहीं बना पाए। बड़ाजात्या ने कहा, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें आगे नहीं बढ़ा पाते। कभी वलाइमैक्स नहीं मिलता, कभी केरेक्टर नहीं बनता। जब तक सब चीजें साथ नहीं आतीं, फिल्म बनाने समझदारी नहीं है। मैंने अब तक सात फिल्में बनाई हैं। मेरा यहीं फैसला है कि जब तक खुद को यकीन न हो, फिल्म नहीं बनाऊगा मुझे खुशी है कि सलमान भाई मेरे साथ है। आज उनकी उम्र में उनके लिए कुछ नया और रिलेवेंट बनाना और बड़ी चुनौती है। सूरज बड़ाजात्या और सलमान न मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन..!, हम साथ साथ हैं और प्रेम रत्न धन पायी जैसी फिल्मों में काम किया है। सूरज बड़ाजात्या और सलमान ने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन..!, हम साथ साथ हैं और प्रेम रत्न धन पायी जैसी फिल्मों में काम किया है।

सलमान की बहुत बड़ी वापसी होगी।



सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' में हुई इस एकट्रेस की एंट्री

सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की मध्य अवेटेड फिल्म 'जटाधारा' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इसको लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी अब फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें फिल्म में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है।
मेकर्स ने फिल्म 'जटाधारा' से अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का लुक जारी कर दिया है। फिल्म में शिल्पा का स्वगत करते हुए मेकर्स ने उनके किरदार के बारे में भी जानकारी दी है। शिल्पा फिल्म में शोभा नाम का किरदार निभाएंगी। उनके किरदार में बारे में जानकारी देते हुए मेकर्स ने बताया कि 'वह सिर्फ लालच से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह उसे परिभाषित भी करती है।' मेकर्स की ओर से जारी किए गए पोस्टर में शिल्पा काली साड़ी पहने हवन कुंड में जलती हुई आग के पास बैठी है। इस दौरान वह आग की ओर चौखते हुए जीभ निकाले हुए हैं। उनके आस-पास कई सारे कंकालों की खोपड़ी भी नजर आ रही है। साथ ही पीछे कई दीप जल रहे हैं। उनके लुक को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई नई प्राचीन वृत्ति का भी रही है।



मराठी आना फायदेमंद है, मगर इसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

इंस्टाग्राम पर अपने कॉमिक कॉन्टेंट के कारण कास्टिंग डायरेक्टर की निगाह में आए कॉन्टेंट क्रिएटर आदित्य ठाकरे को पहली बार के ऑडिशन में ही धड़क 2 जैसी फिल्म में अहम भूमिका मिल गई। मुंबईचा गुलगा आदित्य यहां अपने सफर पर बात करते हैं।

पिता का सपना पूरा किया
कॉन्टेट क्रिएटर से एकटर बनने के सफर के बारे में
वे कहते हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज के दौर में
पैदा हुआ, जब आज हमारे पास सोशल मीडिया और
इंटरनेट है। आप अपना मौका खुद पैदा कर सकते
हैं, जैसे मैंने किया। वरना मेरे पिताजी ने भी
अभिनेता के रूप में काफी संघर्ष किया। वे भी
अनगिनत ऑडिशन का हिस्सा रहे, मगर उन्हें मेरी
तरह मौका नहीं मिला। वे ऑफिस से हाफ डे की
छुट्टी लेकर ऑडिशन के लिए जाया करते थे। आज
मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया है। आपको
शायद सुनकर अजीब तगे मगर मेरे पिता मेरी फिल्म
25-30 बार देख चुके हैं, थिएटर में जाकर। मेरे

मुझे जातिगत भेदभाव का

जातिगत भेदभाव पर वे कहते हैं, मुझे अपनी जाति का पता जिंदगी में दो ही बार चला था, जब मैंने टैंथ और ट्रेल्यू का फॉर्म भरा था। मुझे लगता था कास्ट सिस्टम होता ही नहीं। मगर ये फिल्म करने के बारे में इन मुद्दों को जान पाया और मैं इश्वर्यू के प्रति और सवेदनशील हुआ हूँ। हमने जब उनसे पूछा कि

पहले ऑडिशन में ही पि

रहा है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? विडिओज में तो इसके लिए हिसा का सहारा भी ल हुए दिखाया गया है, तो आदित्य बोले, देखिए, ज तो नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी वायलेंस सख्त खिलाफ हैं। मगर किसी भाषा का आ आपके लिए ही फायदेमंद होता है। अम

आपका प्रास जाना हाता ह, ता आपका
वहाँ फ्रेंच का एजाम देना पड़ता है
इससे आपको काम के और मीवे

अगर मराठी नहीं आती, तो थोड़ी बहुत सीख लें,
उन्हीं का फायदा होगा। जहां तक इस मुद्रे पर
इटरनेट पर आने वाले विडियोज की बात है, तो
30 सेकंड्स की रील पर वया भरोसा किया जा-
सकता है, मगर इतना जरूर कठूँगा कि इस मामले-
में हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए



कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

रेलवे स्टेशन रोड़, प्रेमप्रकाश टॉकीज के पास नवलगढ़

क्रमांक: न.पा.न./2025-26/2465-2470

e-mail-naavalgarh.jaipur@gmail.com

दिनांक: 1/9/2025



राजकुमार सैनी
चेयरमैन



विक्रम सिंह जाखल,
विधायक नवलगढ़

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएँ:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना: नगरीय क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

4. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना:- नगरीय क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ऋण राशि पर 50' अनुदान राशि या अधिकतम 50 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

8. स्वच्छ भारत का सपना साकार, प्लास्टिक मुक्त हो बाजार।

2. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना :- नगरीय क्षेत्र में निवासरत पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

5. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना :- कोई भूखा ना सोये जरूरतमंद व्यक्तियों को 08 रुपये में दोपहर / रात्रि का शुद्ध, ताजा एवं पोषित भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।

3. मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना:- नगरीय क्षेत्र में निवासरत पात्र लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की ऋण राशि 3 चरणों में उपलब्ध करवायी जाती है।

6. जन्म - मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन पालिका में अवश्य करवाये।

7. नगरीय ठोस अपशिष्ट का शत-प्रतिशत वैधानिक प्रबन्धन में सहयोग प्रदान करें।

9. सफाई अपनाओं बिमारी भगाओ।

10. आज ही आदत डालो सुखा एवं गीला कचरा अलग-अलग डालो।

11. आज ही संकल्प ले प्लास्टिक का उपयोग बन्द करे।



देश तभी होगा महान, जब स्वच्छ रहेगा हिन्दुस्तान



श्री रामदेवजी महाराज का
लक्खी मेला-2025 नगर
पालिका नवलगढ़

(राजकुमार सैनी)

अध्यक्ष
नगरपालिका नवलगढ़

(कवंरपाल सिंह)

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़

